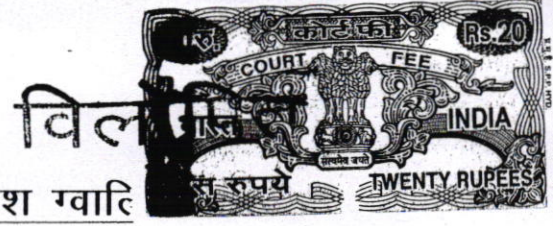


①



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वाटि

म० क० एक / विविध / छतरपुर / भूरा. / 2018

पिविध - 2817/2018/छतरपुर/भू.श

श्री. श्री. राजनी केशव शर्मा 2850
हम आज 7-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 5/6/18 नियत। 5-6-18

राकेश पुत्र स्व० श्री बैजनाथ कायस्थ
निवासीगण छतरपुर तहसील व
जिला छतरपुर म०प्र०

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
7/5/18

—आवेदकगण

विरुद्ध

- 1—मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय छतरपुर
— अनावेदक
- 2—कामता प्रसाद तनय बृजगोपाल ब्रा०
- 3—भक्तभूषण तनय बृजवल्लभ कायस्थ
निवासीगण छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर म०प्र०

—अनोपचारिक पक्षकार

विविध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959
के अन्तर्गत आवेदक के पक्ष में तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर
द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.1975 के परिप्रेक्ष्य में
रिकार्ड/खसरा में पृविष्टि कराने की स्वीकृति वाबत।

माननीय महोदय,

आवेदक का निवेदन निम्न प्रकार है:-

- 1- यह कि प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम पलौठा
स्थित खसरा नंबर 234, 237/1, 239, 244, 753, 712, 713 कुल कित्ता 7

(Handwritten signature)

जिला ग्वालियर
दिनांक 7/5/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-2817/2018/छतरपुर/भू.रा.

राकेश विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-07-2018	<p>1) प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2) आवेदक श्री राकेश के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा पूर्व में दिनांक 06-07-2018 को सुना गया ।</p> <p>3) आवेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 20-04-1975 व अधीक्षक भू-अभिलेख (भू-प्रबंधन) छतरपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अ-6अ/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 04-07-2006 के आधार पर भू-अभिलेख व कम्प्यूटर खसरा में प्रविष्टि कराये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन दिया है ।</p> <p>4) आवेदक के द्वारा तहसीलदार का आदेश आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है । अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने दिनांक 04-07-2006 का आदेश किस अधिनियम व धारा के अंतर्गत किया है । अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा पारित, ^{आदेश} जिसके द्वारा आवेदक को भूमि-स्वामी अधिकार प्रदाय करने की बात की है, वह आदेश प्रथम दृष्ट्या अधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिस पर इस न्यायालय से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है ।</p> <p>5) आवेदक के आवेदन पर कलेक्टर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण की जांच कर विधि अनुसार 3 माह में निर्णय करें । आदेश की एक प्रति कलेक्टर छतरपुर को भेजी जाये ।</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> सदस्य 19.7.18</p>